

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA No.639/2024

**IN THE MATTER OF:**

Sunil Kumar Gupta & Another

Applicant

Versus

Department of Town & Country Planning,  
Haryana and Others

Respondent

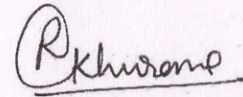
**INDEX**

Sr. No.	Particular	Page No.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 I.E. HARYANA RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY	1-3
2.	<b>ANNEXURE-R/1:</b> Copy of Order NO.22/52/05- 5Power dated 29.07.2005	4-6
3.	<b>ANNEXURE-R/2:</b> Copy of Order dated 14.03.2016	7

Place: Delhi

Date: 03.12.2024

Through



Rahul Khurana, Advocate  
17, Central Lane, Babar Road, Bengali Market,  
New Delhi  
09811894060  
[rkhuranalegal@gmail.com](mailto:rkhuranalegal@gmail.com)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA No.639/2024

**IN THE MATTER OF:**

Sunil Kumar Gupta & Another

Applicant

Versus

Department of Town & Country Planning,  
Haryana and Others

Respondent

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 I.E. HARYANA  
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That present Original Application has been filed by the applicants alleging non-compliance of conditions of Environmental Clearance granted for the project developed by AVL Infrastructure Pvt Ltd. In those alleged non-compliances, absence of solar water heating system in each building block has also been alleged.
2. That answering Respondent No. 5 i.e. Haryana Renewable Energy Development Agency (herein after referred to as 'HAREDA'), is the State Nodal Agency for coordinating all activities relating to Renewable Energy Development including generation of power using non-conventional energy sources as per the Haryana Govt. Policy for Promoting Generation of

Electricity through Renewable Energy Sources Notified vide no.22/69/2005-5P dated 23.11.2005.

It is pertinent here to mention that the Answering Respondent has no relation what so ever with regard to granting licenses for development of houses /buildings/ housing colonies /Group Housing Societies, etc.

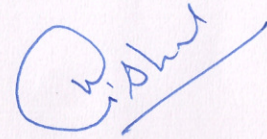
3. That the State Government from time to time while exercising powers under the Energy Conservation Act, 2001 comes out with various orders/ notifications/ directions and amendments therein for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana, such order dated 29.07.2005 with regard to mandatory installation of Solar Water Heating System. Copy of Order NO.22/52/05-5Power dated 29.07.2005 is annexed herewith as **ANNEXURE-R/1**.
4. That the petitioner has enclosed environmental clearance dated 26.11.2015 issued by the State Environment Impact Assessment Authority, Haryana, Panchkula imposing the condition of provision of the solar water system as per norm specified by HAREDA and shall be made operational in each building block.
5. That consequent upon review of the Solar Water Heating system Programme, the State Government vide its order dated 14<sup>th</sup> March, 2016, amended the notification dated 29.07.2005 and

has omitted the mandatory use of solar water Heating systems.  
Copy of Order dated 14.03.2016 is annexed herewith as  
**ANNEXURE-R/2.**

6. That in view of the said amendment, issue of installation of Solar Water Heating System is not under the purview of answering respondent.

In view of facts and submissions made herein above,  
present Original Application may kindly be dismissed qua the  
answering respondent.

Place: Panchkula  
Date: 3<sup>rd</sup> December, 2024



(Vishal Bhatnagar)  
Scientific Engineer-A, New & Renewable Energy Deptt.,  
Haryana & Renewable Energy Development Agency  
(For Respondent No.5)

Scientific Engineer (A)  
HAREDA, Panchkula



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 29, 2005 (SRAVANA 7, 1927 SAKA)

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 29 जुलाई, 2005

संख्या 22/5/2005-5 विद्युत.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के फलोत्पादक उपयोग तथा इसके संरक्षण के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :—

1. सौर जल तापीय प्रणाली का आज्ञापक उपयोग

1. सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग भवनों के निम्नलिखित प्रवर्गों में आज्ञापक होगा, अर्थात् :—

(क) रद्योगों में जहाँ प्रसंस्करण के लिये गर्म पानी अपेक्षित है।

(ख) हस्पताल और नर्सिंग होम जिसमें सरकारी हस्पताल भी शामिल हैं।

(ग) होटल, मोटल और समारोह हाल।

(घ) जल बैरकें और केन्रीमें।

(ङ) सनूह आवास समितियों/हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्थापित हाउसिंग काम्प्लेक्स।

(च) नगरपालिका समितियों/निगमों तथा हुडा के सेक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी आवासीय भवन।

(छ) सभी सरकारी भवनों, आवासीय विद्यालयों, शैक्षणिक महाविद्यालयों, होस्टलों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन काम्प्लेक्सों तथा विश्वविद्यालय इत्यादि।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) विशिष्टियों के अनुसार श्रेष्ठ रूप से डिजाईन किये गये उत्तम गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये राज्य में सौर जल तापीय प्रणालियों की आपूर्ति तथा स्थापना के लिये अनुमोदित स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

3. सभी सम्बन्धित विभाग जैसे नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग, आवास बोर्ड, जन-स्वास्थ्य विभाग और वास्तुकला विभाग आदेश जारी होने की तिथि से दो मास के भीतर सौर जल तापीय प्रणालियों का उपयोग करने के लिये अपने नियम/उप-विधियां को संशोधित करेंगे।

Price : Rs. 5.00

(2983)

4. ये विभाग राज्य सरकार के निर्णय को मॉनिटर करने तथा लागू करने की प्रगति अक्षय ऊर्जा विभाग को निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक आधार पर भेजने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर भी नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे।
2. सरकारी भवनों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों/बोर्डों/निगमों में काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी०एफ०एल०) का आजापक उपयोग
1. सरकारी सेक्टर/सरकारी सहायता प्राप्त सेक्टर/बोर्ड तथा निगमों/स्वायत निकायों में सभी नये निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में इन्केंडेसेंट बल्बों के प्रयोग पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध किया जाता है।
  2. यह आजापक होगा कि विद्यमान भवनों में खराब इन्केंडेसेंट बल्बों को जब बदला जम्मे तो केवल काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी०एफ०एल०) से ही बदला जायेगा।
  3. विद्युत उपयोगिता में, नये कनेक्शन अथवा नया लोड जारी/स्वीकृत करते समय पारम्परिक बल्ब के स्थान पर सी०एफ०एल० के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक उपांतरण करना होगा।
3. कृषि क्षेत्र में आई०एस०आई० मार्कड मोटर पम्प सेट, पावर कैपिसीटर, फुट/रिफ्लैक्स वाल्व का आजापक उपयोग
1. सभी नये ट्यूबवैल कनेक्शनों के लिये आई०एस०आई० मार्कड पम्प सेट्स तथा एससरीज का उपयोग आजापक होगा।
  2. राज्य में केवल आई०एस०आई० मार्कड पम्प सेट्स का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये इस आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ट्यूबवैल कनेक्शनों के लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक संशोधन करेगा।
4. ऊर्जा कुशल भवन डिजाईन को बढ़ावा देना
1. सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले सभी नये भवनों में 30 जून, 2006 से ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाईन धारणा जिसमें अक्षय ऊर्जा तकनीक भी शामिल है, सम्मिलित करेंगे।
  2. वास्तुकला विभाग मविष्य में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले सभी भवनों में ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाईन धारणा को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा। वास्तुकला विभाग में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र निर्मित किये जाने वाले सभी नये भवनों की योजना/मानचित्रों की जांच करने तथा सुनिश्चित करने के लिये कि ऊर्जा कुशल भवन निर्माण डिजाईन धारणा की सभी विशेषताओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया के लिये एक समिति गठित की जायेगी।
  3. वास्तुकला विभाग इन उपायों के समन्वय तथा मॉनिटरिंग के लिये एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा जो निदेशक, अक्षय ऊर्जा विभाग को इस बारे में प्रगति की सूचना देगा।
- इस मामले में पूर्व में जारी किये गये सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुये यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

एस० सी० चौधरी,  
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
अक्षय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT  
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 29th July, 2005

No. 22/52/05-5P.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana, namely :—

1. Mandatory use of Solar Water Heating Systems

1. The use of solar water heating systems will be mandatory in the following categories of buildings, namely :—
  - (i) Industries where hot water is required for processing.
  - (ii) Hospitals and Nursing homes including Government Hospitals.

- (iii) Hotels, Motels and Banquet halls.
- (iv) Jail Barracks, Canteens.
- (v) Housing Complexes set up by Group Housing Societies/Housing Boards.
- (vi) All residential buildings built on a plot of size 500 square yards and above falling within the limits of municipal committees/corporations and Haryana Urban Development Authority sectors.
- (vii) All Government buildings, Residential Schools, Educational Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, District Institutes of Education and Training, Tourism Complexes and Universities etc.

2. Haryana Renewable Energy Development Agency will act as an approved source for supply and installation of solar water heating systems in the State to ensure the installation of optimally designed quality systems as per the specifications.

3. All the line departments like Town and Country Planning Department, Urban Development Department, Public Works Department (Building and Roads), Housing Board, Public Health Department and Architecture Department will amend their rules/bye-laws within a period of two months from the date of issue of this order to make the use of solar water heating systems mandatory.

4. These departments will also designate a district and a state level nodal officer to monitor and report the progress of enforcement of the State Government decisions to the Department of Renewable Energy, Haryana on Quarterly basis in the prescribed format.

#### 2. **Mandatory use of Compact Fluorescent Lamp (CFL) in Government Buildings/Government Aided Institutions/Boards/Corporations**

1. The use of incandescent lamps in all new buildings/institutions constructed in Government sector/Government Aided sector/Board and Corporation/Autonomous bodies is banned with immediate effect.

2. It will be mandatory that in existing buildings the defective incandescent lamps when replaced, would be replaced by only compact fluorescent lamps (CFL).

3. Power utilities will affect necessary modification in the load demand notices within two months time from the date of issue of this order to promote the use of Compact Fluorescent Lamps instead of conventional bulbs while releasing/sanctioning new connections/loads.

#### 3. **Mandatory use of ISI marked Motor pump sets, Power capacitor, Foot/Reflex valves in Agriculture Sector**

1. For all new tubewell connections, the use of ISI marked pump sets and accessories will be mandatory.

2. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam/Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam will make the amendments in the load demand notices for tubewell connections within two months time from the date of issue of this order to ensure use of only ISI marked pumps in the State.

#### 4. **Promotion of Energy Efficient Building Design**

1. All the new buildings to be constructed in the Government/Government Aided sector will incorporate energy efficient building design concepts including Renewable Energy Technologies with effect from 30th June, 2006.

2. The Architecture Department will ensure the incorporation of energy efficient building design concepts in all buildings to be constructed in future in the Government/Government Aided sector. A committee shall be formed in the Architecture Department to examine all new building plans/drawings to be constructed in the Government/Government Aided sector to ensure that all the features of the energy efficient building design concepts, have been incorporated in these.

3. The Architecture Department will designate a nodal officer for coordination and monitoring of these measures who will report the progress in this regard to the Director, Renewable Energy Department, Haryana.

The above orders supersede all previous orders in this matter and come into force with immediate effect.

S. C. CHAUDHARY,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Renewable Energy Department

**हरियाणा सरकार**

अक्षय ऊर्जा विभाग

**आदेश**

दिनांक 14 मार्च, 2016

**संख्या 22/52/2005-5 विद्युत.**— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग, आदेश संख्या 22/52/05-5 विद्युत, 29 जुलाई, 2005 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग, आदेश संख्या 22/52/05-5 विद्युत, दिनांक 29 जुलाई, 2005 में पैरा 1, “सौर जल तापीय प्रणाली आज्ञापक उपयोग” का लोप कर दिया जाएगा ।

अंकुर गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
अक्षय ऊर्जा विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT****RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT****Order**

The 14th March, 2016

**No.22/52/2005-5 Power.**— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No.22/52/05-5Power, dated the 29th July, 2005, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Renewable Energy Department, Order No. 22/52/05-5Power, dated the 29th July, 2005, **Para 1, “Mandatory use of Solar Water Heating Systems”** shall be omitted.

ANKUR GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Renewable Energy Department.

**हरियाणा सरकार**

अक्षय ऊर्जा विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 14 मार्च, 2016

**संख्या 19/4/2016-5 विद्युत-&** हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016 तैयार की है। इस नीति को प्रभावी करने के लिए, विभिन्न नीतियों, नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन, जहां आवश्यक हो, शीघ्रता से संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा ।

**हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, 2016**

अध्याय-1

**परिचय****1.1 सौर ऊर्जा ही क्यों**

शुरुआत करने के लिए हमें रहने की जरूरत है। यदि विकल्प हो तो हम एक सतत तरीके से अच्छी तरह से रह सकते हैं । सौर ऊर्जा को भविष्य के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है । भारत में विशेष रूप में यह अंदाज लगाया जा सकता है कि कोयले का भंडार वर्ष 2040-50 से अधिक समय तक नहीं रहेगा । दुनिया भर में तेल का भंडार भी घट रहा है और अपने आप में प्रदूषण के कारकों के साथ जुड़ा हुआ है ।

**सौर ऊर्जा:-**

- स्थायी और अक्षय